

(घ) क्या पार्सलों को चार दिन के लिए रख छोड़ना रेलवे की लापरवाही नहीं है;

(ङ) क्या यह सच है कि रेलवे प्रशासन ने स्वयं 80 प्रतिशत हानि का अनुमान लगाया है; और

(च) रेलवे द्वारा जारी किये गये मूल्यांकन प्रमाणपत्र को तथा इसके फलस्वरूप पड़ने वाले दायित्व को स्वीकार न करने के क्या कारण हैं ?

रेलवे मंत्री (श्री० रामसुभग सिंह) : (क) यह सच नहीं है। इन परेपणों वाला पार्सल यान 4-4-1966 को 5-10 बजे अजमेर पहुंचा और उमी दिन 14 डाउन से आगे रवाना कर दिया गया। इसे चार दिन तक अजमेर में नहीं रोका गया लेकिन यह दो दिन तक दिल्ली यार्ड में रुका रहा।

(ख) जी नहीं। 3 डाक / एक्सप्रेस और 2 सवारी गाड़ियां हैं जो रोजाना अजमेर से दिल्ली के लिए रवाना होती हैं।

(ग) भाग (क) के उत्तर को देखने हुए सवाल नहीं उठता।

(घ) किसी भी स्थान पर यह यान चार दिनों तक नहीं रुका रहा। दिल्ली यार्ड में दो दिन की जो देर हुई, उसमें हो सकता है, कुछ लापरवाही हुई हो, लेकिन इस समय इसका निश्चित रूप से मत्पापन नहीं किया जा सकता।

(ङ) जी हां।

(च) मूल्यांकन केवल मुपुर्दगी के समय माल को हुई क्षति का पता लगाने और उसका सत्यापन करने के लिए किया जाता है। क्षति कितनी हुई, यह केवल एक तथ्य का प्रश्न है। मूल्यांकन के आचार पर मुपुर्दगी की मंजूरी देने और कितनी क्षति हुई इसका प्रमाण-पत्र जारी करने का अर्थ यह नहीं है कि दायिता स्वीकार

कर ली गयी। दायिता तो बाद में दावा निबटाने वाले प्राधिकारी द्वारा मामले के तथ्यों को देखते हुए और सम्बन्धित कानून के आधार पर निश्चित की जाती है।

इस मामले में, दिल्ली यार्ड में यान के दो दिन रुके रहने के बावजूद रास्ते की दूरी को देखते हुए परेपणों के परिवहन में लगा समय अधिक नहीं है, अतः दायिता स्वीकार नहीं की गयी।

12.28 hrs.

#### CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

#### ABOLITION OF WEST BENGAL LEGISLATIVE COUNCIL

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali) : Sir, I call the attention of the Minister of Law to the following matter of urgent public importance and I request that he may make a statement thereon :

"The resolution passed by the West Bengal Legislative Assembly to abolish the West Bengal Legislative Council."

THE MINISTER OF LAW AND SOCIAL WELFARE (SHRI GOVINDA MENON) : Mr. Speaker, Sir, under Article 169 (1) of the Constitution, if the Legislative Assembly of a State passes a resolution providing for the abolition of the Legislative Council of a State having such a Council or for the creation of such a Council in a State having no such Council, and with the required majority, Parliament may by law provide for the abolition or the creation of a Council as the case may be. No such law shall be deemed to be an amendment of the Constitution.

On receipt of the resolution reported to have been passed by the Legislative Assembly of the State of West Bengal, Government will take up the matter for suitable action.

SHRI S. K. TAPURIAH : There is no doubt that lofty ideas and good intentions

[Shri S. K. Tapuriah]

were in the mind of the Constituent Assembly when the provision was made for having Second Houses in the States and at the Centre. Unfortunately these Upper Houses have been brought to a position of mere ridicule by Governments by converting them into abodes of defeated politicians and rejected ministers and using the Houses as contraptions for bringing those men into ministries who did not otherwise have the guts to face the electorate.

What recently happened in the Rajya Sabha election in Uttar Pradesh was that there was a dispute about the list of the Congress Party candidates and the names were manipulated in such a way that it must have definitely embarrassed the President also when he had to make nomination....

MR. SPEAKER : This is about West Bengal Council.

SHRI S. K. TAPURIAH : The disease that was started by the Congress appears to have contaminated certain other political parties also in some other States. The net result is that as things stand today these Upper Houses do not serve the purpose for which they were once intended. The only redeeming feature is that at least at this late stage the Congress seems to have realised the uselessness of these Chambers and so when this question came in the West Bengal Assembly, the Congress Party supported this Resolution. In view of their change of mind, sir, may I know whether in those States where the Congress has a majority and where there are Second Chambers, like Andhra Pradesh, Maharashtra and Mysore, the Party on its own will bring forward resolutions for abolition of Second Chambers and not wait for their defeat and formation of new Governments to support this move ?

MR. SPEAKER : You are asking about Andhra Pradesh, Maharashtra and Mysore.

SHRI GOVINDA MENON : And nothing about West Bengal... (*Interruptions*).

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (Balrampur) : The question is whether the Congress Party in Parliament will bring forward such a Resolution ?

MR. SPEAKER : Shrimati Ila Pal Choudhuri.

SHRIMATI ILA PALCHOUDHURI (Krishnagar) : The question deals only with West Bengal and not any other State. I would like to know one thing : Now that the West Bengal Assembly has passed the Resolution, how soon will the Parliament also pass the law—will it be passed during the Budget Session—so that the Upper House in West Bengal can be abolished ?

SHRI GOVINDA MENON : What Parliament has to pass is an ordinary law and I said, as soon as we get the official report of the Resolution of the West Bengal Assembly, we will take action.

SHRI INDRAJIT GUPTA (Alipore) : In this session ?

SHRI GOVINDA MENON : I said 'as soon as'.

श्री देवेन सेन : ( आसनसोल ) अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा गया है :

It is felt in New Delhi that there may be some other States wanting to abolish their Upper Houses and it will be better to wait for their reaction.

मैं इसकी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि सरकार ने तो मान लिया कि पश्चिमी बंगाल का जो प्रस्ताव हुआ उसके मुताबिक काम किया जायेगा लेकिन हो सकता है कि इसमें विलम्ब किया जाये और दूसरी परिस्थितियों को पैदा होने का मौका दिया जाये इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या उस पर फोरन अमल किया जायेगा ?

SHRI GOVINDA MENON : Including West Bengal, there are nine States today where there are Legislative Councils. We shall not wait as to what the action in the

other States would be, to take action regarding West Bengal.

श्री शिव चन्द्र झा ( मधुवनी ) : अध्यक्ष महोदय, अपर हाउस एक पॅरासिटिक बाडी हो गई है, सुपरफुलस हो गई है, उसका खत्म होना जरूरी है। लोवर हाउस समाज के निर्माण के लिए यदि कोई बुनियादी कदम उठाता है तो अपर हाउस उसमें एक रूकावट के रूप में आ जाता है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊँ कि इंग्लैंड में मि० एटली जब हाउस कामन्स में स्टील नेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में बिल ला रहे थे तो हाउस आफ लार्ड्स की ओर से रूकावट हुई इसलिए उन्होंने उसके पहले ही एक दूसरा विधेयक लाकर हाउस आफ लार्ड्स के हाथ पैर बांध दिए और इस प्रकार से स्टील नेशनलाइजेशन के काम को आगे बढ़ाया लेकिन बंगाल की सरकार आज उममें भी आगे जा रही हैं। संयुक्त विधायक दल की सरकार बंगाल के पुनर्निर्माण के लिए बुनियादी कदम उठाना चाहती है और इसीलिए उसने अपर हाउस को खत्म करने का रास्ता अपनाया है। बंगाल सरकार का यह फैसला एक प्रगतिवादी कदम है, जनतंत्र के अनुकूल है, विधान के अनुकूल है। अब मैं सीधा प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या बंगाल सरकार की ओर से आपको इसकी औपचारिक रूप से सूचना मिली है ? यदि हाँ, तो आपने क्या जवाब दिया है और उस जवाब को क्या आप इस मदन के समापटल पर रखेंगे ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या इसी घादार्श के मुताबिक आप राज्य सभा को भी समाप्त करने के सम्बन्ध में कदम उठायेंगे ?

MR. SPEAKER : The hon. Minister has answered it already and said that officially he has not received it, and the moment he receives it, he will take action. The hon. Member has repeated the same question which was asked earlier. As regards Rajya Sabha, that does not arise now.

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : It does arise, because people have been elected to Rajya Sabha from West Bengal also.

MR. SPEAKER : But not by the Council; they have been elected by the Assembly.

श्री मधु लिये (मुंगेर) : अध्यक्ष महोदय, विधान परिषदें अप्रत्यक्ष चुनावों के द्वारा चुनी जाती हैं। उनको बर्खास्त करने के लिए हम लोग एक अरसे से मांग कर रहे हैं। मुझे खुशी है और मैं पश्चिम बंगाल की सरकार और वहाँ की विधान सभा का अभिनन्दन करना चाहता हूँ कि उन्होंने यह काम किया है। इसके पहले मध्य प्रदेश में भी वहाँ की गैर कांग्रेसी सरकार ने प्रस्ताव किया था। मिश्रा साहब विधान परिषद का निर्माण करना चाहते थे लेकिन वहाँ की संयुक्त विधायक दल की सरकार ने और विधान सभा ने प्रस्ताव किया कि विधान परिषद नहीं बनेगी। पिछले दो वर्षों से जबसे गैर कांग्रेसी सरकारों का राज्यों में निर्माण हुआ है, और विधान सभाओं की मार्फत, जनता की राय की अभिव्यक्ति होती है लेकिन कई दफा मैंने देखा हैं—मद्रास, बिहार और उत्तर प्रदेश में—कि इन लोक नियुक्त सरकारों के खिलाफ विधान परिषदों ने प्रस्ताव किए हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि पश्चिमी बंगाल और पंजाब तथा मध्य प्रदेश ने जो किया है क्या उसकी रोशनी में मन्त्री महोदय ममी राज्यों के मुख्य मंत्रियों और विरोधी दलों के प्रतिनिधियों को बुलाकर समूचे देश में विधान परिषदों को समाप्त करने के लिए कदम उठायेंगे ?

SHRI GOVINDA MENON : The scheme of the Constitution is very clear. It is left to the States themselves to suggest to us regarding the abolition of the Legislative Councils...

AN HON. MEMBER : What about Rajya Sabha ?

SHRI GOVINDA MENON : ...and I think the Government of India will not

[Shri Govinda Menon]

stand in the way of the views of the Government of the States, and I think the inclination of the House and Parliament also will be to honour the decision of the States in this respect.

12.37 hrs.

RE: CALLING-ATTENTION-NOTICES (QUERIES)

SHRIMATI GAYATRI DEVI (Jaipur) : I am sorry to intrude on the time of the House. But yesterday I had asked for a calling-attention-notice regarding the *dharna* by the Opposition MLA's in Rajasthan. Today, in view of the news that we have received that there has been a lathi-charge in front of the Assembly in Jaipur, I would like to raise a few points here. First of all, technically, I admit that this is a State subject. But in view of the fact that the Rajasthan Home Minister has said that because the commission was appointed during President's rule it was not necessary for the present Rajasthan Government to accept it and secondly he has also said that this involves the UP police and he had written to them and he has not got a reply, and, therefore, his hands are tied, I would like to suggest that morally the Centre is also involved, for, firstly this commission was appointed during President's rule and secondly the UP police are also involved.

Therefore, under article 256 of the Constitution, I would beg of the Home Ministry to recommend to the Rajasthan Government that the Beri Commission's report should be accepted *in toto*.

Also, the other day, Shri M. J. Limaye was told by the Home Minister that he would inform the House whether or not the Rajasthan High Court had been given an assurance by the State Advocate-General that the full implementation of the Beri Commission's report would be ensured. So, I would request you to ask the Home Minister to lay a statement on the Table of the House.

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान में जो परिस्थिति पैदा हुई है उस पर सदन को चर्चा करने का मौका दिया जाय। परिस्थिति विस्फोटक है जिससे हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए संकट पैदा हो सकता है। गृह मंत्री से कहा जाये कि वे वक्तव्य दें और फिर उस पर सदन को चर्चा करने का मौका दिया जाये।

SHRI S. M. BANERJEE : Regarding Durgapur....

MR. SPEAKER : I am coming to Durgapur also.

श्री कंवर लाल गुप्त (दिल्ली सदर) : अध्यक्ष महोदय, ...

MR. SPEAKER : I have called the leader of the hon. Member's party already. I cannot call every Member from every party.

The point is this. There were two or three calling-attention-notices which were important. For instance, there was one regarding Durgapur. Where the Central Reserve Police were functioning in the State and the State Government said that they did not know anything about it. It is an important matter. I had considered it and I was going to admit it. Would the hon. Member not wait till then....

SHRI INDRAJIT GUPTA : This is a very serious matter involving the Centre-State relations. You should not relegate it to a calling-attention-notice.

MR. SPEAKER : The hon. Member must hear me in full. Tomorrow, the Home Ministry's Demands are coming up, and if hon. Members so feel they can throw out those Demands or reject those Demands. During the discussion of the budget Demands, not only here but in any Parliament, there is an opportunity for the Opposition to throw out the Government, and, therefore, adjournment motions are not admitted....